जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 15 संख्याः 140 प्रभात हिण्डौन सिटी, गुरुवार 23 मार्च, 2023 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

खाली हाथ लौटे चीन के राष्ट्रपति रूस की यात्रा से!

यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए उनका प्रस्ताव, यूक्रेन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन ने एक सिरे से पूर्णतया अस्वीकार किया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मार्च। मध्य-पूर्व में ईरान और सऊदी अरब के बीच एक दीर्घकालीन विरोध को हल करने में कूटनीतिक सफलता प्राप्त कर फूले नहीं समा रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे को लेकर माना जा रहा था कि वह वहां भी ऐसी ही सफलता प्राप्त करेंगे।

यूक्रेन युद्ध जब से शुरु हुआ है, रूस कूटनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ने के बाद चीन पर लगातार निर्भर रहा है।

इसके भारत के लिए भी मायने हो सकते हैं क्योंकि विश्व में कहीं भी चीन के हितों को लेकर होने वाले किसी भी संघर्ष में बीजिंग का समर्थन करने में रूस का आधिकाधिक झुकाव रहेगा। चीन इसके बदले में भारत के साथ लगती अपनी सीमा पर कलह बढ़ाने में अधिक सक्रिय होगा और इस प्रकार वह अपनी गिरी हुई घरेलू स्थिति से विश्व का ध्यान डायवर्ट कर सकेगा।

- यूक्रेन ने कहा, चीन का शांति प्रस्ताव रूस के आक्रमण को उचित ठहराने का प्रयास है। तथा, रूस द्वारा यूक्रेन की भूमि को हथियाने को ''लैजिटमाइज़'' कराने का प्रयास है।
- रूस ने अपनी मध्यस्थता से सऊदी अरब व ईरान की पुरानी दुश्मनी खत्म करायी है, अतः विश्व को काफी आशा थी कि, चीन, रूस व यूक्रेन के बीच भी शांति स्थापित करवायेगा, पर, राष्ट्रपति शी की रूस यात्रा, इस मामले में पूर्णतया निराशाजनक रही।
- इसी निराशा के कारण, रूस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कटाक्ष किया, चीन केवल अपना खुद का मित्र है, किसी और का मित्र नहीं हो सकता।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात को लेकर शी के बहुप्रचारित मॉस्को दौरे की पृष्ठभूमि में चीन ने यूक्रेन में शांति स्थापना के लिए एक कूटनीतिक पेपर प्रकाशित किया था। शी के मॉस्को दौरे के संदर्भ में पुतिन ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि यूक्रेन संकट को हल करने में चीन के प्रस्ताव अहम होंगे।

तथापि, चीन के प्रस्तावों को कहीं से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली और खासतौर पर, यूक्रेन से तो बिल्कुल भी नहीं। यूक्रेन ने इनके प्रकाशन के साथ ही इनकी यह कहकर आलोचना की थी कि चीन का पेपर सिर्फ रूस की स्थिति मजबूत करने के लिए है। आलोचना इस बात को लेकर थी कि पेपर में यह उल्लेख किए बिना युद्ध विराम का आ ान किया गया है कि रूस के सैनिकों को यूक्रेन के क्षेत्र से बाहर चले जाना चाहिए।

यूरोपीयन यूनियन ने चीन के प्रस्तावों पर विचार करने की जरूरत नहीं समझी और उन्हें खारिज कर दिया। उसने कहा कि इनका उद्देश्य यूक्रेन में भूमि पर कब्जा करने के रूस के इरादों को और मजबूत करना भर है। इसी तरह, अमेरिका ने यह कहते हुए इन्हें खारिज कर दिया कि युद्ध विराम की चीन की घोषणा का उद्देश्य रूस को पुर्नसंगठित होने और अपना आक्रमण पुनः शुरु करने के लिये समय उपलब्ध करवाना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, पर पैट्रोल, डीज़ल के दाम सिर्फ बढ़ रहे हैं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मार्च। कांग्रेस प्रवक्ता प्रो. गौरव वल्लभ ने कहा है कि मोदी सरकार में ईंधन की गतिशील कीमतें बिल्कुल ऐसी है ''मानो चित हम जीते, पट तुम हारे।'' उन्होंने कहा कि ईंधन के कीमत-निर्धारण की नीति के तहत, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जब-जब कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो उसका लाभ अंतिम/मूल उपभोक्ता को नहीं होता।

- कांग्रेस की तरफ से पार्टी प्रवक्ता प्रो. गौरव वल्लभ ने पूछा कि, पैट्रोल, डीज़ल के दाम गतिशील हैं, पर ये लगातार चढ़ क्यों रहे हैं, कभी घटते क्यों नहीं।

गौरव ने कहा, ''हम एक्साइज ड्यूटी को कम करने के लिये नहीं कह रहे है, जो पैट्रोल के मामले में मई, 2014 की 9.2 रू. लीटर से अब 19.9 रू. लीटर हो गई है तथा डीज़ल की एक्साइज ड्यूटी 3.46 रू. से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत ने पलटवार किया ब्रिटेन पर

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मार्च। भारत सरकार ने नई दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन तथा ब्रिटिश हाई कमिश्नर के आवास के बाहर के सुरक्षा बैरियर्स हटा दिये हैं। सरकार की इस कार्यवाही को बदले की कार्यवाही के रूप में देखा जा रहा है।

रविवार को, लंदन-स्थित भारतीय उच्चायोग पर लगा भारतीय झंडा किसी खालिस्तान-समर्थक प्रदर्शनकारी ने हटा दिया था। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, भारत सरकार ने भारत में ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया था तथा लंदन की उस घटना को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया था। भारतीय

- नई दिल्ली स्थित ब्रिटेन के हाई कमिशन कॉम्पलैक्स से सुरक्षा वापस ली।
- जैसा कि विदित ही है, लंदन में भारतीय कमिश्नर के कॉम्प्लैक्स पर खालिस्तान समर्थकों ने तोड़-फोड़ की तथा भारत का झण्डा उतार कर खालिस्तान का झण्डा फहरा दिया था।
- भारत इस कृत्य को ब्रिटेन की प्रशासनिक शिथिलता तथा हाई कमिशन परिसर की सुरक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान न देना मानता है।

अधिकारियों ने भी ब्रिटिश सरकार पर कूटनीतिक परिसरों की सुरक्षा के प्रति ''उदासीनता'' बरतने का आरोप लगाया था। विदेश मंत्रालय ने इस ''जैसे को तैसे'' कदम पर कोई अधिकृत प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने भी ''सुरक्षा संबंधी मामलों''

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आंध्र में मु.मंत्री व पूर्व मु.मंत्री एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की होड़ में

वाय.एस.आर. कांग्रेस के नेता व वर्तमान मु.मंत्री जगन रेड्डी ने पूर्व मु.मंत्री चन्द्रबाबू नायडू पर 3 सौ सत्तर करोड़ रूपये डकारने का सीधा आरोप लगाया

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मार्च। तेलंगाना या कर्नाटक, जहाँ प्रमुख राजनैतिक दलों के बीच की बड़ी राजनैतिक लड़ाइयाँ राष्ट्रीय चर्चाओं का विषय बन रही हैं, के विपरीत, आंध्र प्रदेश इस मामले में ज्यादा चर्चित नहीं है, हालाँकि सत्तारूढ़ वाय.एस.आर.सी.पी. तथा तेलुगू देशम पार्टी के बीच की लड़ाई भी उतनी ही उग्र और भीषण स्तर पर पहुँच रही है तथा आरोपों-प्रत्यारोपों का सिलसिला रोज़ की बात है। अगर विपक्षी तेलुगू देशम पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री वाय.एस. जगमोहन रेड्डी सरकार का शासन निरंकुश एवं फासिस्ट है जिसमें जजों तक को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी ने पहली बार पिछले मुख्यमंत्री का नाम लेते हुये, उन पर 370 करोड़ रू. से अधिक के घोटाले में सीधे तौर पर लिप्त होने का आरोप लगाया है।

- जगन रेड्डी के अनुसार ''स्किल डवलपमैंट प्रोजैक्ट'' का यह पैसा सीधा विदेश गया और वहां से चन्द्रबाबू नायडू की ''डमी कम्पनियों'' के अकाउन्ट्स में आया।
- अभी आंध्र में चुनाव एक साल दूर हैं, और कीचड़ उछालने की होड़ इस स्तर पर पहुंच गयी, जब चुनाव सिर पर होंगे तो, आरोपों का स्तर और कितना नीचे जायेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री एन. चन्द्राबाबू नायडू ने दुख व्यक्त करते हुये कहा है कि राज्य में ''आपातकाल जैसी'' स्थिति चल रही है तथा सरकार सभी मोर्चों पर विफल हो चुकी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री राज्य को पीछे धकेल रहे हैं। सत्तारूढ़ दल ने इस आरोप की उतनी ही तीखी प्रतिक्रिया दी है।

आंध्र प्रदेश में प्रमुख दल चुनावी मोड़ में आ चुके हैं। आंध्र के प्रमुख विरोधी दलों के बीच मीडिया में उग्र टकराव तथा उत्तेजित बहसें हो रही हैं, वहीं जमीन पर भी उत्तेजनापूर्ण टक्करें चल रही हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष लोकसभा चुनावों के साथ ही होने हैं तथा इसलिये वहाँ राजनैतिक हलचलें बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ ही भाजपा यह टोह ले रही है कि क्या वह आंध्र में प्रवेश कर सकती है। भाजपा सैलिब्रिटीज को अपने साथ लाकर, जनता तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। भाजपा सुपर स्टार पवन कल्याण, जो मेगा स्टार चिरंजीवी के भाई हैं, का सहयोग लेने का मानस पूरी तरह बना चुकी है। ज्ञातव्य है कि मनमोहन सिंह सरकार में केन्द्रीय मंत्री रह चुके हैं।

जब एन.टी. रामाराव ने राजनीति में आकर, कांग्रेस का नाटीकय रूप से सर्वनाश कर दिया था, तभी से ये सैलिब्रिटीज, ये स्टार आंध्र प्रदेश की राजनीति में अपना भाग्य आजमाते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वांछित तथा जबरदस्त सफलता नहीं मिल सकी है। पवन कल्याण के भाई चिरंजीवी ने एक पार्टी बनाई थी लेकिन उनकी पार्टी 294 में से सिर्फ 18 सीटें ही जीत सकी थी तथा बाद में उसका विलय कांग्रेस में हो गया था।

जहाँ नये दलों के आने से राजनीति का अखाड़ा रोचक होता जा रहा है, वहीं मुख्य लड़ाई सत्तारूढ़ वाय.एस.आर., सी.पी. तथा विपक्षी तेलुगू देशम पार्टी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मैंने कभी लंदन, पेरिस, अमेरिका व जर्मनी से हस्तक्षेप करने की बात नहीं कही'

राहुल गांधी ने एक इन्टरव्यू में कहा, ''वे मानते हैं कि, भारतीय प्रजातंत्र के संकट का समाधान भी भारत ही निकालेगा, कोई और नहीं''

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मार्च। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र के संकट के संबंध में कहा कि यह हमारे देश की समस्या है और इसका समाधान हमारे देश के भीतर ही खोजना होगा। इसका समाधान बाहर से नहीं आ सकता।

उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि जैसा सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके विपरीत उन्होंने लंदन, पेरिस, अमेरिका या बर्लिन की सरकारों से कभी भी हस्तक्षेप करने को नहीं कहा।

इस सप्ताह की शुरूआत से ही चल रही इन अटकलों के बारे में कि यदि विपक्ष गौतम अडानी के प्रकरण में जॉइन्ट पार्लियामैन्टरी कमेटी (जे.पी.सी.) से जांच की अपनी मांग को वापस ले लेता है तो भाजपा लोकतंत्र पर की गई उनकी टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग को वापस ले लेगी, राहुल ने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों मुद्दे एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ''हम ऐसी किसी भी सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं है।''

- चर्चा है कि, अगर कांग्रेस अडानी के प्रकरण में जे.पी.सी. की मांग त्याग देगी तो, सरकार भी राहुल द्वारा माफी मांगने की जिद छोड़ देगी।
- इस चर्चा पर राहुल ने कहा, ये दोनों अलग-अलग बाते हैं, हम इस सौदे के लिये तैयार नहीं हैं तथा जे.पी.सी. के गठन की मांग कभी नहीं छोड़ेंगे।
- जयराम रमेश ने राहुल के कथन का समर्थन करते हुए कहा, अडानी आखिर इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गये कि, उनको बचाने के लिये संसद नहीं चलने दी जा रही तथा जे.पी.सी. का गठन नहीं हो रहा।

कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञों का एक पैनल अडानी केन्द्रित है, जो अडानी केन्द्रित है, जो सिर्फ अडानी से ही प्रश्न पूछेगा ''लेकिन हम अडानी से प्रश्न पूछना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार से प्रश्न पूछे जाएं। हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न केवल जे.पी.सी. ही पूछ सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल उन पर विचार तक नहीं करेगा।'' उन्होंने आशंका जतायी की सुप्रीम कोर्ट का पैनल सरकार को क्लीन चिट दे देगा।

उन्होंने यहां ए.आई.सी.सी. मुख्यालय पर बुधवार को आयोजित एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वह तीन प्रश्न प्रतिदिन के हिसाब से मोदी से इस बारे में अब तक 100 प्रश्न पूछ चुके हैं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)